RNI NO : RAJHIN/2020/79632

खबर का महारथी

खबर ,विज्ञापन एवं अपने लेख प्रकाशित करवाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते है। 8209621934

वर्ष - 5 अंक 49 साप्ताहिक | जयपुर बुधवार , 10 दिसंबर 2025 | Web: khabarkamaharathi.com | पृष्ठ : 4 | मूल्य : 5 रुपये

एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में ... 4

4 नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में ...

एक नजर

राजस्थान की उप-मुख्यमंत्री दीया कुमारी की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात

खबर का महारथी

जयपुर। उप-मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मंगलवार को नई दिल्ली में संसद सत्र के दौरान संसद भवन स्थित कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री मोदी से प्रदेश में विकास और जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री का प्रेरणादायी मार्गदर्शन, सकारात्मक दृष्टि और राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमेशा नई ऊर्जा प्रदान करती है। उनकी सादगी, जनसेवा का जुनून और नेतृत्व क्षमता मानव कल्याण के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

उड्डयन मंत्रालय ने कैंसिलेशन कम करने के लिए इंडिगो के संचालन में 10 प्रतिशत कटौती का दिया आदेश

खबर का महारथी

नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट्स कैंसिल होने से हजारों यात्रियों को हुई परेशानी के बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को एक बार फिर इंडिगो एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स को तलब किया। जानकारी के अनुसार इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और मंत्रालय के सचिव समीर सिन्हा मौजूद थे। इंडिगो अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यात्रियों की देखभाल, रिफंड की स्थिति और पायलट और क्रू रॉस्टर की वर्तमान स्थिति को लेकर चर्चा की गई। उड्डयन मंत्रालय द्वारा एयरलाइन के सीईओ के साथ बैठक के बाद कैंसिलेशन कम करने के लिए इंडिगो के संचालन में 10 प्रतिशत कटौती का आदेश दिया। बैठक के बाद उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर

बताया कि पिछले हफ्ते इंडिगो के क्रू रोस्टर, फ्लाइट टाइम-टेबल और अपर्याप्त संचार के आंतरिक कुप्रबंधन के कारण कई यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। जांच और आवश्यक कार्रवाई जारी रहने के साथ ही इंडिगो के शीर्ष प्रबंधन के साथ स्टेबलाइजेशन उपायों की समीक्षा के लिए एक बैठक हुई थी।

नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि आज फिर इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को मंत्रालय में बुलाया गया। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर तक प्रभावित उड़ानों के लिए 100 प्रतिशत रिफंड कर दिया गया है। शेष रिफंड और सामान की सुपुर्दगी जल्द से जल्द पूरी करने के सख्त निर्देश दिए गए। मंत्रालय ने इंडिगो के सभी मार्गों पर उड़ानों की संख्या में कटौती करने का फैसला किया है। इससे एयरलाइन के संचालन को स्थिर करने और कैंसिलेशन की घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 10 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया गया है। इसका पालन करते हुए इंडिगो पहले की तरह अपने सभी गंतव्यों पर उड़ान जारी रखेगी। इंडिगो को मंत्रालय के सभी निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें किराया सीमा और यात्री सुविधा उपाय शामिल हैं। इससे पहले उड्डयन मंत्री ने एक्स पर बताया कि इंडिगो के परिचालन में व्यवधान के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के कारण, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए 3 दिसंबर से सभी हवाई अड्डों पर स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। आज रात स्थिति का व्यापक आकलन करने के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई।

प्रवासी राजस्थानी चैप्टर्स के साथ संवाद- राज्य सरकार निवेशकों को दे रही हरसंभव सहयोग : मुख्यमंत्री भजनलाल

खबर का महारथी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में खनन, ऊर्जा, शिक्षा, पर्यटन तथा स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति और निवेश की अपार संभावनाएं हैं। देश-विदेश के बड़े निवेशक प्रदेश के इन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं लेकिन प्रवासी राजस्थानियों का अपनी मातृभूमि में निवेश कर विकसित राजस्थान की यात्रा में सहभागी बनना एक सुखद अहसास है। हम निवेशकों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए उन्हें हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में देश-विदेश के आठ प्रवासी राजस्थानी चैप्टर्स के साथ संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान में सामाजिक व आर्थिक विकास से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने और निवेश हेतु प्रोत्साहित करने के

लिए चैप्टर्स के प्रतिनिधियों की सराहना की। शर्मा ने कहा कि आज बुधवार, 10 दिसम्बर को जेईसीसी, सीतापुरा में आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए चैप्टर्स की सक्रियता प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने देश और विदेश में अपनी मेहनत और लगन से राजस्थान का नाम रौशन किया है। साथ ही, उन्होंने अपनी मिट्टी से जुड़ाव रखकर प्रदेश में भी सामाजिक सरोकारों में बढ़-चढ़कर भागीदारी की है। उन्होंने कहा कि एनआरआर की भागीदारी को और अधिक बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक डैशबोर्ड का निर्माण किया है। इसमें प्रदेश के सभी जिलों में गैप-एरियाज को चिन्हित किया गया है, ताकि प्रवासी राजस्थानी अपने गांव, शहर, जिले में भामाशाहों के सहयोग से होने वाले कार्यों में सुगमता से योगदान देकर अपनी मातृभूमि के विकास में भागीदार बन सकें।

एनआरआर पॉलिसी से निवेश का बनेगा ईको सिस्टम –

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने 'राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग' का गठन किया है। यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों और राज्य सरकार के बीच संवाद और सहयोग के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध करवाएगा जिससे प्रवासियों का अपनी मातृभूमि से जुड़ाव और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नॉन-रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी ऑफ राजस्थान-2025 निवेश, व्यापार, ज्ञान के आदान-प्रदान, शोध आदि में एनआरआर के योगदान को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगी। यह नीति प्रवासी राजस्थानियों के निवेश को गति देने के लिए राज्य में एक बेहतर इकोसिस्टम का निर्माण करेगी।

इस दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, रियाद , काठमांडू , रांची, गुवाहाटी, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोयम्बटूर चैप्टर्स के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

आदर्श ग्राम योजना की राज्य स्तरीय बैठक निरोगी रहना मानव जीवन का सर्वोत्तम सौभाग्य : डॉ. प्रेमचंद बैरवा

खबर का महारथी

जयपुर। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि निरोगी रहना मानव जीवन का सर्वोत्तम सौभाग्य है। प्रकृति ने हमें स्वस्थ रहने के लिए अनेक अनमोल औषधियों एवं प्राकृतिक उपचार विधियों का वरदान दिया है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों और जीवनशैली को आमजन का अभिन्न हिस्सा बनाना है। डॉ. बैरवा मंगलवार को शासन सचिवालय में आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के संबंध में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में निरोगी रहने, रोगों की रोकथाम करने और प्रकृति आधारित उपचार पद्धतियों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर नागरिक प्राकृतिक और संतुलित जीवनशैली अपनाकर स्वस्थ, सशक्त और ऊर्जा से भरपूर जीवन

जी सके। **आयुष्मान गांवों को 11 लाख रुपए का प्रोत्साहन–**

आयुर्वेद विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के पहले चरण में प्रत्येक जिले की 5 ग्राम पंचायतों का चुनाव किया गया हैं। इसके बाद आयुष्मान आरोग्य मंदिर वाली ग्राम पंचायतों को इसमें सम्मिलित किया जायेगा। इन पंचायतों में 18 स्वास्थ्य सूचकांकों पर काम किया जायेगा और इन सूचकांकों की पूर्ण पालना वाली ग्राम पंचायतों को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

आरोग्य सखी से होगा गाँव-गाँव आयुष्मान–

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में आरोग्य मित्र एवं आरोग्य सखियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा। वे वरिष्ठ नागरिकों, बालिकाओं, शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को वनौषधि परिचय, घरेलु उपचार, आहार-विहार, योग व्यायाम, बीपी व ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, नशामुक्ति जैसे सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषयों का ध्यान रखेगे।

बैठक में आयुष, पंचायती राज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, शिक्षा विभाग के अधिकारी और यूनिसेफ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। साथ ही सम्बंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े।

राजस्थान में फिर बढ़ेगी सर्दी : मौसम विभाग ने 4 जिलों में जारी किया अलर्ट

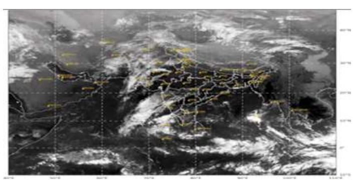

खबर का महारथी

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर शीतलहर का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 10 दिसंबर से कोल्ड-वेव का प्रभाव दिखाई देने लगेगा। इसका सबसे अधिक असर शेखावाटी के जिलों–सीकर, चूरू, झुंझुनूं–सहित नागौर में देखने को मिलेगा। इन चारों जिलों के लिए विभाग ने दो दिनों का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जताई गई है। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 1 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने के बाद सोमवार को राज्य के सभी शहरों में आसमान बिल्कुल साफ रहा और तेज धूप खिली। पाली, कोटा, बारां, पिलानी और जयपुर सहित कई शहरों में धूप की वजह से तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राज्य में सोमवार का सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 32.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम केंद्र जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 19 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। इनमें सबसे कम तापमान फतेहपुर में 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा। जैसलमेर में भी तापमान अचानक गिरकर 9.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि शेखावाटी और आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम अगले एक सप्ताह तक साफ रहेगा और शीतलहर से राहत बनी रहेगी।

राज्य में यूरिया डाइवर्जन को रोकने के लिए 24 दिसम्बर तक विशेष अभियान- डॉ. किरोड़ी लाल

खबर का महारथी

जयपुर। राजस्थान विधानसभा जयपुर। राज्य के कृषकों को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज एवं पेस्टिसाइड समय पर मिले एवं इनकी कालाबाजारी व जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर गुण नियंत्रण अभियान चलाया जाता है। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि राज्य में पिछले वर्ष 2024-25 में रबी की बुवाई 95 लाख 85 हजार हैक्टेयर में की गई थी। रबी 2025-26 में 105 लाख 60 हजार हैक्टेयर में बुवाई की जा चुकी है। विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष रबी फसल का रकबा बढ़ा है। कृषकों को रबी 2025-26 में उच्च गुणत्ता के कृषि आदान उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में रबी गुण नियंत्रण अभियान 23 सितम्बर से 15 नवम्बर तक चलाया गया। इस अभियान के तहत कृषि आदानों के कुल 304 निर्माताओं व विक्रेता परिसरों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कुल 4

हजार 87 नमूने लेकर विश्लेषण हेतु विभिन्न प्रयोगशालाओं में भिजवाये गये हैं। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान उर्वरक नियंत्रण आदेश, बीज नियंत्रण आदेश एवं कीटनाशी अधिनियम की धाराओं का उल्लघंन करने पर 56 निर्माता, विक्रेता परिसर के लाइसेंस निलंबित तथा 8 फर्मों के लाइसेंस निरस्त किये गये हैं। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री ने कहा कि राज्य में यूरिया डाइवर्जन को रोकने हेतु 24 दिसम्बर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ताकि पात्र किसानों को समय पर यूरिया मिल सके। उक्त अभियान के तहत यूरिया डाइवर्जन के 420 कट्टे जब्त करने की कार्रवाई की गई है। कृषि आयुक्तालय स्तर से भी टीमों का गठन किया गया है जो कि जिलों में औचक निरीक्षण करने की कार्यवाही कर रहे हैं। सभी जिला स्तर के विभागीय अधिकारियों को सघन निरीक्षण कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त कृषि आदान उपलब्ध करवाने के लिए विभाग निरंतर प्रयासरत है एवं इस प्रकार की ठोस कार्रवाई लगातार जारी रहेंगी।

इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने पर कांग्रेस नेताओं ने सरकार को घेरा, संसद में चर्चा की मांग

खबर का महारथी संवाददाता

नई दिल्ली। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने और इससे यात्रियों को होने वाली परेशानी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का कहना है कि इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, ये छोटा मामला नहीं है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले में कुछ ऐसा हुआ है जो छिपाया जा रहा है। इस तरह के मामले की जांच होनी चाहिए। मंत्री कह रहे हैं कि हम कदम उठा रहे हैं, लेकिन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ अंदर दिक्कतें चल रही हैं, जिसकी वजह से यह समस्या हुई है। इसकी जांच होनी चाहिए और डीजीसीए की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। सरकार की अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए और सरकार को भी इस पर नियंत्रण रखना होगा।

कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल का कहना है कि क्या पूरी गलती सिर्फ इंडिगो की है? सरकार की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई होगी? सरकार ने जो रेगुलेशन लागू किया है, क्या उसमें कोई खामी थी? अचानक सब ठप कैसे हो सकता

है? ऐसा सुनने में आया है कि सरकार ने रेगुलेशन वापस ले लिया है।

उन्होंने कहा कि एविएशन के सेक्टर में रिसर्च करके कमर्शियल एयरलाइन को सफल कैसे बनाया जा सकता है, इस पर कदम उठाना चाहिए। इतनी एयरलाइन्स अब तक बंद हो चुकी हैं क्योंकि वे इसे मेंटेन नहीं कर पाई। एक तरफ आप किराए को कम रखने की बात करते हैं और दूसरी तरफ एयरलाइन टर्बाइन फ्यूल के दाम दुनिया में सबसे अधिक रखते हैं। आपको इसका ध्यान रखना होगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि इंडिगो के हालात पर पिछले दो दिनों में राज्यसभा और लोकसभा में सरकार का बयान आया है। इसकी पूरी जिम्मेदारी एक निजी कंपनी के मालिक की है। ऐसा लग रहा है कि सरकार की कोई जिम्मेदारी और डीजीसीए की कोई भूमिका ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हजारों यात्री परेशान हुए और उन्हें बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इस बीच पायलट को लेकर सरकार जो कानून लाई, उसे भी बदल दिया गया। न पायलट को राहत, न ग्राहक को राहत, न सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी, बस कंपनी के मालिक को एक नोटिस दे दिया गया। सरकार समझती है कि उनकी जिम्मेदारी बस इतनी ही है।

उन्होंने कहा कि जब लोकसभा में मंत्री ने बयान दिया तो पूरा विपक्ष इससे असहमत था और इसलिए हमने वॉकआउट किया। हमारी मांग स्पष्ट है कि सरकार सिर्फ मंत्री के बयान से भाग नहीं सकती, इस पर चर्चा होनी चाहिए। यह मामला सिर्फ एक हफ्ते में फ्लाइट्स के कैंसिल होने का नहीं है बल्कि इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। गौरव गोगोई ने कहा कि सदन के अंदर एविएशन इंडस्ट्री पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज से उड़ेंगे, लेकिन कहां? न चप्पल पहनने वाला उड़ पाया और न ही शूज पहनने वाला। यह जो स्थिति हुई है, इस पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए।

हस्तशिल्प न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं, बल्कि आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं : राष्ट्रपति मुर्मू

खबर का महारथी संवाददाता

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को नई दिल्ली में वर्ष 2023 और 2024 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कला हमारे अतीत की स्मृतियों, वर्तमान के अनुभवों और भविष्य की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य चित्रकला या मूर्तिकला के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता रहा है। कला लोगों को संस्कृति से जोड़ती है। कला लोगों को एक-दूसरे से भी जोड़ती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यदि हमारी सदियों पुरानी हस्तशिल्प परंपरा जीवंत और संरक्षित बनी हुई है, तो इसका श्रेय पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे कारीगरों की प्रतिबद्धता को जाता है। हमारे कारीगरों ने अपनी कला और परंपरा को बदलते समय के साथ ढाला है और साथ ही मूल भावना को भी जीवित रखा है। उन्होंने अपनी प्रत्येक कलात्मक रचना में देश की मिट्टी की खुशबू को संजोए रखा है। उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं, बल्कि आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। यह क्षेत्र

देश में 32 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। उल्लेखनीय है कि हस्तशिल्प से रोजगार और आय प्राप्त करने वाले ज्यादातर लोग ग्रामीण या दूरदराज के इलाकों में रहते हैं। यह क्षेत्र रोजगार और आय का विकेंद्रीकरण करके समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक सशक्तीकरण के लिए हस्तशिल्प को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को सहायता प्रदान करता रहा है। हस्तशिल्प न केवल कारीगरों को आजीविका का साधन प्रदान करता है, बल्कि उनकी कला उन्हें समाज में पहचान और सम्मान भी दिलाती है। इस क्षेत्र के विकास से महिला सशक्तीकरण को भी बल मिलेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल में 68 प्रतिशत महिलाएं हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि हस्तशिल्प उद्योग की सबसे बड़ी ताकत प्राकृतिक और स्थानीय संसाधनों पर इसकी निर्भरता है। यह उद्योग पर्यावरण के अनुकूल है और इसका कार्बन उत्सर्जन कम है। आज दुनियाभर में पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ जीवनशैली की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में, यह क्षेत्र स्थायित्व में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुई कि जीआई टैग दुनिया भर में भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों की पहचान को मजबूत कर रहा है। उन्होंने सभी हितधारकों से अपने अनूठे उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि जीआई टैग उनके उत्पादों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करेगा और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाएगा। 'एक जिला, एक उत्पाद' पहल हमारे क्षेत्रीय हस्तशिल्प उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को भी मजबूत कर रही है। हमारे कारीगरों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचित ज्ञान, समर्पण और कड़ी मेहनत के बल पर, भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय हस्तशिल्प की मांग में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। यह क्षेत्र युवा उद्यमियों और डिजाइनरों को उद्यम स्थापित करने के बेहतरीन अवसर प्रदान करता है।

संपादकीय ....

अधिकारों से आगे सम्मान की संस्कृति

हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाने वाला Human Rights Day सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक राष्ट्रों की आत्मा की परख है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए यह दिन केवल मानवाधिकारों के 'उल्लेख' का नहीं बल्कि उनके 'अनुपालन' और 'सुरक्षा' की प्रतिबद्धता का दिन है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत ने संविधान में मौलिक अधिकारों की मजबूत नींव रखी, पर आज चुनौती अधिकारों से अधिक 'अधिकारों के सम्मान की संस्कृति' को विकसित करने की है।

पिछले वर्षों में मानवाधिकार चुनौतियाँ केवल पारंपरिक नहीं रहीं—डिजिटल निजता, साइबर बुलिंग, लैंगिक हिंसा, जातीय भेदभाव, मानव तस्करी, श्रमिक अधिकार और बाल संरक्षण अब प्रमुख मुद्दों के रूप में उभरे हैं। ह्ष्ट्रक्रक्के अनुसार भारत में हर वर्ष लगभग 2.70 लाख महिलाएँ हिंसा की किसी न किसी घटना की शिकार होती हैं, वहीं हर 8 मिनट में एक बच्चा खो जाता है, जिनमें से बड़ी संख्या मानव तस्करी से जुड़ जाती है। ये आंकड़े बताते हैं कि विकास की रफ्तार के साथ-साथ मानवाधिकारों का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है।

भारत ने मानवाधिकारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण सुधार किए—नई शिक्षा नीति 2020 में समान अवसर, कश्मीर में 370 हटने के बाद मानवाधिकारों की बहाली की नई आधारशिला, डिजिटल इंडिया के माध्यम से सेवाओं तक समान पहुँच, और गरीबों के लिए करोड़ों लाभार्थियों को योजनाओं से सीधे जोड़कर अधिकारों का सशक्तिकरण। लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बड़ी हैं—न्यायिक देरी, कानूनों का जटिल ढाँचा, ट्रैफिकिंग नेटवर्क, जेलों में ओवरक्राउडिंग, और पुलिस सुधार की अधूरी प्रक्रिया आज भी मानवाधिकार सुरक्षा के सामने दीवार बनकर खड़ी है।

Human Rights Day के संदर्भ में भारत के लिए यह समय मूल्य आधारित विकास मॉडल अपनाने का है—जहाँ आर्थिक विकास के साथ क़ानूनी, सामाजिक और डिजिटल अधिकारों की भी समान सुरक्षा सुनिश्चित हो। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की राह तब ही पूर्ण होगी जब मानवाधिकार केवल 'अधिकार' नहीं बल्कि 'व्यवहार' बन जाएँ।

- बृजमोहन शर्मा

दिवाली को यूनेस्को की अमूर्त विश्व विरासत में मिली जगह

खबर का महारथी

भारत की सांस्कृतिक गाथा में दिवाली केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रकाश, समरसता और आध्यात्मिक ऊर्जा का सतत प्रवाह है – ऐसी धरोहर जो पीढ़ियों से भारतीय समाज की आत्मा में बसती आई है। अब इसी दिव्य परंपरा को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक सूची में शामिल कर आधिकारिक रूप से विश्व विरासत का दर्जा दिया है। यह निर्णय न केवल भारत के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति की गहराई, मानवीय मूल्यों और लोक परंपरा की शक्ति को उजागर करने वाला ऐतिहासिक कदम भी है।

दिवाली की यह मान्यता उस विशाल सांस्कृतिक निरंतरता को दर्शाती है, जो अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर उम्मीद की जीत का शाश्वत संदेश देती है। दिवाली हमेशा से इस बात का प्रतीक रही है कि समाज में समता, उत्साह और एकता की रोशनी हर घर तक पहुँचे – कुम्हार, मूर्तिकार और हस्तशिल्पी से लेकर व्यापारी तक, सबकी खुशियों में समान भागीदारी हो।

इस वर्ष अयोध्या में सरयू किनारे 26.17 लाख दीयों की उजास ने दुनिया को चकित किया, और यही ऐतिहासिक रिकॉर्ड वैश्विक सांस्कृतिक मंचों को प्रभावित करने वाली वह चिंगारी बना जिसने दीवाली को विश्व विरासत दर्जा दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया। इससे पहले भारत की वैदिक मंत्रोच्चार परंपरा, रामलीला, दुर्गा पूजा, छाऊ नृत्य और कुंभ मेले समेत 15 अमूर्त धरोहरें इस सूची में शामिल हैं।

यूनेस्को का यह निर्णय ऐसे समय आया है जब भारत दिल्ली में इंटर-गवर्नमेंटल कमेटी फॉर इंटैन्जिबल हेरिटेज की 20वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है– एक ऐसा मंच जहां दुनिया भर की जीवित परंपराएँ, लोक-कला, त्योहार और सांस्कृतिक प्रणालियाँ सुरक्षित रखने की दिशा में कदम उठाए जाते हैं। दिवाली का वैश्विक मंच पर इस रूप में उभरना निस्संदेह भारत की सांस्कृतिक कूटनीति और विरासत संरक्षण के बढ़ते प्रभाव का संकेत है।

> **"भारत की सांस्कृतिक गाथा में दिवाली केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रकाश, समरसता और आध्यात्मिक ऊर्जा का सतत प्रवाह है – ऐसी धरोहर जो पीढ़ियों से भारतीय समाज की आत्मा में बसती आई है। अब इसी दिव्य परंपरा को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक सूची में ..."**

यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची का उद्देश्य उन परंपराओं को संरक्षित करना है जो भौतिक रूप से दिखाई न दें, लेकिन किसी समाज की पहचान और संस्कृति की नींव होती हैं। ऐसे समय में जब वैश्वीकरण कई परंपराओं को चुनौती दे रहा है, दिवाली का यह दर्जा सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने का मजबूत संदेश देता है। भारत अब दुनिया को यह समझाने की स्थिति में है कि दीपावली केवल उत्सव नहीं—यह मानवता को जोड़ने वाली, आत्मिक शुद्धि और सामाजिक समानता का गहरा दर्शन है।

दिवाली के विश्व धरोहर बनने के साथ ही भारत की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। यह सुनिश्चित करना होगा कि यह परंपरा आधुनिकता की भीड़ में खो न जाए और आने वाली पीढ़ियाँ इस त्योहार की आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक महत्ता और सामाजिक संदेश से उतनी ही गहराई से जुड़ी रहें, जितना आज तक जुड़ी रही हैं।

दरअसल, दिवाली विश्व को यह याद दिलाने का सामर्थ्य रखती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश की एक छोटी लौ भी परिवर्तन की शुरुआत कर सकती है। यही संदेश, यही दर्शन और यही आध्यात्मिक ऊर्जा अब वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान को नई चमक दे रही है।

डॉ. ओपी शर्मा
इंडिया गेट, जयपुर

बिजली चोरी से चल रहे थे बीएमसी, ईंट भट्टे, पोल्ट्री फार्म व पेट्रोल पम्प

खबर का महारथी

जयपुर। जयपुर डिस्कॉम की सतर्कता शाखा ने मंगलवार को जयपुर ग्रामीण के राडावास व खेजरोली क्षेत्र में सतर्कता जांच कार्यवाही की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेन्द्र कुमार शर्मा एवं अधीक्षण अभियंता बी.एल.शर्मा ने बताया कि सहायक अभियंता उपासना सिंह के नेतृत्व में टीम ने राडावास विद्युत सब डिवीजन क्षेत्र के अंतर्गत बी.एम.सी, ईंट भट्टा, पोल्ट्री फार्म व आवासीय परिसरों में 7 जगहों पर बिजली चोरी के मामले पकडे तथा खेजरोली सब डिवीजन क्षेत्र के अंतर्गत 1 पेट्रोल पम्प पर भी बिजली चोरी पकडी। इन 8 मामलों में कुल 18.81 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है। राडावास के हनुतपुरा स्थित एक बीएमसी की वीसीआर भरी गई और करीब 4.58 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया। राडावास के महारखुर्द स्थित 2 ईंट भट्टां पर क्रमशः 2.18 लाख व 1.16 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है। राडावास के हनुतिया एवं हनुतपुरा स्थित 3 आवासीय परिसरों में बिजली चोरी पर 2.89 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है। हनुतपुरा एक पोल्ट्री फार्म पर 2.59 लाख रूपए जुर्माना लगाया गया है। खेजरोली के सिंगोद खुर्द स्थित एक पेट्रोल पम्प पर 5.37 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है। संबंधित व्यक्तियों एवं उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर दिये गये हैं। टीम द्वारा मौके से सभी अवैध केबिल को जब्त कर लिया गया है।

दिल्ली कार ब्लास्ट केसः NIA ने जम्मू-कश्मीर के जंगलों में तलाशी ली

खबर का महारथी संवाददाता

श्रीनगर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारियों ने मंगलवार को दिल्ली कार ब्लास्ट केस के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के जंगलों में तलाशी अभियान चलाया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एनआईए टीम ने जम्मू-कश्मीर पुलिस की मदद से 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके के सिलसिले में जिले के जंगल वाले इलाके में तलाशी शुरू की है। सूत्रों ने बताया कि एनआईए टीम तलाशी के लिए सही जगह का पता लगाने के लिए दो आरोपियों, डॉ. आदिल राथर और जसीर बिलाल वानी को भी अपने साथ लाई है।

जम्मू-कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद इलाके में स्थानीय डॉक्टरों द्वारा चलाए जा रहे एक व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। इसके बाद दो साजिशकर्ताओं, डॉ. आदिल राथर और डॉ. मुजम्मिल गनई को गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरा साजिशकर्ता, डॉ. उमर नबी, गिरफ्तारी से बच निकला। बाद में, डॉ. उमर नबी ने लाल किले के पास अपनी विस्फोटक से भरी कार में धमाका किया। इस धमाके में वह भी मारा गया। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में कहा था कि आतंकी साजिश की जड़ एक लव अफेयर में थी। उन्होंने कहा कि आतंकी साजिश करने वालों में से एक, डॉ. मुजम्मिल गनई का एक लोकल लड़की के साथ अफेयर था। जब मुजम्मिल ने अपनी गर्लफ्रेंड को नजरअंदाज करना शुरू किया, तो दोनों के बीच दूरियां आ गईं।

इसके बाद, नाराज गर्लफ्रेंड पुलिस के पास गई और बताया कि जैश-ए-मोहम्मद संगठन के पोस्टर डॉ. मुजम्मिल ने चिपकाए थे। मुजम्मिल की गिरफ्तारी से एक मौलवी की गिरफ्तारी हुई और फिर पुलिस ने पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में पुलिस ने डॉ. उमर फारूक और उनकी पत्नी शहजादा को भी गिरफ्तार किया। इस जोड़े पर अपनी सोशल स्टेटस का इस्तेमाल करके युवाओं को आतंकवाद की ओर लुभाने का आरोप है। वहीं, शहजादा अख्तर पर महिलाओं के आतंकी ग्रुप 'दुख्तरान-ए-मिल्लत' को फिर से शुरू करने की कोशिश करने का आरोप है, जो 2018 में अपनी मुखिया आसिया अंद्राबी की गिरफ्तारी के बाद बंद हो गया था।

भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई

खबर का महारथी

यूँ 9 दिसंबर का International Anti-Corruption Day भारत के लिए एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि भ्रष्टाचार वह अदृश्य दीमक है जो विकास की हर ईंट को भीतर से खोखला करती है। विश्व बैंक के अनुसार भ्रष्टाचार का अर्थव्यवस्था पर सीधा असर होता है और विकासशील देशों की GDP का 2-4% हिस्सा हर साल भ्रष्टाचार में नष्ट हो जाता है। भारत भी इस वैश्विक चुनौती का केंद्र रहा है, लेकिन पिछले दशक में सरकार, एजेंसियों और न्यायिक सुधारों ने इसे नियंत्रित करने की दिशा में कई गंभीर प्रयास किए हैं।

भारत में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आधार रहा था—कैश अर्थव्यवस्था, बेनामी संपत्तियाँ, घोटालों का धीमा निपटारा और तंत्र में पारदर्शिता की कमी। पिछले वर्षों में डिजिटल सिस्टम, DBT, GST, फास्टैग, ई-टेंडरिंग और आधार आधारित पहचान ने भ्रष्टाचार को बड़ी हद तक सीमित किया है। एक अनुमान के अनुसार DBT के माध्यम से 3.6 लाख करोड़ रुपये की बचत केवल बिचौलियों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर हुई।

लेकिन भ्रष्टाचार केवल प्रशासनिक नहीं, सामाजिक समस्या भी है। छोटे स्तर की रिश्वतखोरी से लेकर बड़े आर्थिक अपराध तक—इनका प्रभाव विकास से लेकर न्याय व्यवस्था तक पर पड़ता है। ED और CBI द्वारा हाल के वर्षों में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में की गई बड़ी बरामदगी इस बात का संकेत है कि भारत अब बड़े आर्थिक अपराधियों को भी कानून के दायरे में लाने की दिशा में निर्णायक मोड में है।

फिर भी चुनौती कम नहीं है। निम्न स्तर पर भ्रष्टाचार, टेंडर स्कैम, पुलिस-प्रशासनिक रिश्वतखोरी, और राजनीतिक वित्तीय अपारदर्शिता अभी भी देश की प्रगति को धीमा करते हैं। विकसित भारत 2047 के सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ 'सिस्टम + समाज' दोनों की लड़ाई जरूरी है। इसके लिए पारदर्शी शासन, न्यायिक सुधार, तेज़ जांच, संपत्ति ज़ब्ती कानून, और डिजिटल इकोसिस्टम को और मजबूत करना होगा। International Anti-Corruption Day इस बात का स्मरण कराता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है – और भारत अब इस लड़ाई के निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका है।

संजू शर्मा
स्वतंत्र पत्रकार, लेखिका एवं वरिष्ठ टिप्पणीकार

मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में पशुपालन विभाग की योजनाओं का प्रभावी विस्तारः पशुपालन मंत्री

खबर का महारथी संवाददाता

जयपुर। पशुपालन, डेयरी, गोपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पिछले दो वर्षों में पशुपालन विभाग ने पशु स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को व्यापक और सरल बनाया है। विभिन्न जिलों में नए पशु चिकित्सा संस्थानों की स्थापना की गई । पुराने संस्थानों का आधुनिकीकरण किया गया, जिससे पशुओं के उपचार, टीकाकरण और षल्य क्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार आया। विभिन्न पदों पर रिकार्ड भर्ती मंत्री कुमावत ने बताया कि विभाग में विभिन्न पदों पर बड़ी नियुक्तियां हुई हैं। दो सालों में जितनी संख्या में नियुक्ति हुई है वह एक रिकार्ड है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की स्पष्ट सोच है कि मैन पावर की कमी की वजह से विभाग का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए और पशुपालकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वर्ष 2019 से लम्बित भर्ती प्रक्रिया को बिना देरी किए पूर्ण कर 727 पशु चिकित्साधिकारियों को नियमित नियुक्ति प्रदान की गई है। प्रदेश के आठ जिलों में आवश्यक अस्थायी आधार पर 500 पशुधन सहायकों एवं 125 पशु चिकित्साधिकारियों की भर्ती की गई है। साथ ही 1100 पदों पर पशु चिकित्साधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है।

कुमावत ने बताया कि केवल पशु चिकित्सक ही नहीं बल्कि तकनीकी कार्मिकों की भी कमियों को दूर करने के लिए भी प्रयास किए गए। इस दिशा में राज्य में 5778 पशु परिचरों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है शेष 774 की नियुक्तियां भी इसी माह कर दी जाएंगी। पशुधन निरीक्षक के 2783 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद दस्तावेज प्रमाणीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। शीघ्र ही नियुक्ति के आदेश जारी किये जायेंगे।

पशु चिकित्सा संस्थानों का सुदृढ़ीकरण

पशुपालन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि समस्त जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में विभागीय पशु चिकित्सा संस्था उपलब्ध हो ताकि स्थानीय पशुपालकों को उनके नजदीक ही पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इसी प्रयास के क्रम में 50 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों को बहुउददेशीय पशु चिकित्सालयों में, 101 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में तथा 151 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया है, साथ ही दो नवीन पशु चिकित्सालय एवं 700 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्वीकृत किये गये हैं, जिसके तहत कुल 2423 नवीन पद सृजित किये गये हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 100 पशु चिकित्सालयों एवं 475 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों में आधारभूत संरचना विकसित किये जाने के लिए 200 करोड़ रुपये की लागत से भवन निर्माण, फर्नीचर एवं उपकरण आदि उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल ग्रामीण आजीविका, पशुधन विकास और किसान कल्याण के लिहाज़ से निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने दी बड़ी सौगात : नौनेरा वृहद एवं परवन अकावद पेयजल परियोजनाओं को मिली मंजूरी

खबर का महारथी संवाददाता

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य के प्रत्येक परिवार को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य पर तेजी से कार्य कर रहे है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना एवं परवन-अकावद पेयजल परियोजना के कार्यादेश जारी किए गए हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर कोटा-बूंदी-झालावाड़-बारां जिले के लाखों लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। सरकार द्वारा इन परियोजनाओं पर कुल 5 हजार 184 करोड़ रुपये व्यय होंगे। नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना के माध्यम से कोटा एवं बूंदी जिले के 749 गांव एवं 6 कस्बों के 1 लाख 13 हजार 287 परिवारों को हर घर जल उपलब्ध होगा। सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए 1 हजार 661.14 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। परियोजना के अन्तर्गत कोटा एवं बूंदी के लिए 1 इन्टैक पंप गृह निर्माण, 3 जल शोधन संयंत्र निर्माण, 14 स्वच्छ जलाशय तथा 137 उच्च जलाशय का निर्माण होगा। इसके माध्यम से कोटा एवं बूंदी जिले के लिए 58.45 किलोमीटर लम्बी रॉ वॉटर राइजिंग मेन पाइप लाइन बिछाई जाएगी। नौनेरा वृहद परियोजना से 4 हजार 506.89 किलोमीटर लम्बी राइजिंग मेन, कलस्टर वितरण एवं ग्रामीण वितरण पाइप लाइन का निर्माण होगा। साथ ही, कोटा एवं बूंदी में कुल 14 पंप गृह निर्माण किए जाएंगे।

इसी प्रकार, परवन-अकावद पेयजल परियोजना से झालावाड़-बारां-कोटा जिले के लाखों परिवार लाभान्वित होंगे। इसके माध्यम से बारां के 907, कोटा के सांगोद विधानसभा क्षेत्र 184 तथा झालावाड़ के 311 गांव सहित कुल 1 हजार 402 गांव व 276 ढाणियों को लाभ होगा तथा इन जिलों के लगभग 1 लाख 52 हजार 437 परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। इस परियोजना के लिए 3 हजार 523.16 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। परियोजना के अन्तर्गत कोटा एवं झालावाड़ के लिए 2 इन्टैक पंप गृह निर्माण, 2 जल शोधन संयंत्र निर्माण, 41 स्वच्छ जलाशय तथा 276 उच्च जलाशय का निर्माण होगा। इसके माध्यम से बारां-कोटा-झालावाड़ जिले के लिए कुल 661 किलोमीटर लम्बी मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन बिछाई जाएगी। परवन अकावद पेयजल परियोजना से 9 हजार 477 किलोमीटर लम्बी राइजिंग मेन, कलस्टर वितरण एवं ग्रामीण वितरण पाइप लाइन का निर्माण होगा।

इन दोनों परियोजनाओं को अगस्त 2027 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। जल जीवन मिशन प्रदेश में हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के लिए एक अति महत्वकांक्षी परियोजना है। जेजेएम के अन्तर्गत इन दोनों परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से राज्य सरकार के आमजन तक स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के संकल्प को गति मिलेगी।

अरिहंत ग्लोबल ने मनाया 12वाँ वार्षिकोत्सव, 'मिशन 100 थीम' के साथ ऊर्जा से भरपूर भव्य उत्सव बढ़ता राजस्थान

खबर का महारथी संवाददाता

जयपुर। डिजिटल सेवाओं, मोबाइल संचार सुविधाओं और आधुनिक तकनीकी समाधानों में अग्रणी संस्था अरिहंत ग्लोबल ने इस वर्ष अपना 12वाँ वार्षिकोत्सव अत्यंत जोश, उत्साह और पारिवारिक वातावरण में मनाया। इस वर्ष समारोह का मुख्य विषय 'मिशन 100 थीम - ऊर्जा के साथ उत्सव' रखा गया, जिसका उद्देश्य आने वाले समय में अधिक अनुभवी मेंटर्स, सदस्यों द्वारा सशक्त, प्रशिक्षित और ऊर्जावान टीम का निर्माण करना, डिजिटल रोजगार सृजन , फ्रेंचाइजी सेगमेंट में प्रवेश करना है।

यह भव्य समारोह काश्वी बैंक्वेट, खंडेलवाल ढाबेवाला, जयपुर में आयोजित हुआ, जहाँ संस्था के सभी कर्मचारियों के साथ उनके परिवारजन भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिससे कार्यक्रम का वातावरण और अधिक आत्मीय व उल्लासपूर्ण हो गया।

समारोह में उद्योग, शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र के सम्मानित अतिथियों– डॉ. अरुण अग्रवाल, जगदीश सोमानी, मनीष जैन, अंकुर जोशी, मुकुल गोस्वामी, प्रो. त्रिलोक जैन एवं गौमाता सेवार्थ ग्रुप के वरिष्ठ सदस्यों—ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सभी अतिथियों ने अरिहंत ग्लोबल की 12 वर्षों की विकास यात्रा, टीम-संस्कृति, नवाचार तथा समाज के प्रति योगदान की सराहना की।

संस्थान के संस्थापक राहुल कुमार जैन और सुनीता जैन ने अपने उद्बोधन में अरिहंत ग्लोबल द्वारा विकसित किए गए अनेक प्रमुख डिजिटल मंचों और सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से– नवउद्यमियों, लघु और मध्यम उद्योगों, युवाओं के कौशल विकास, और तकनीकी दक्षता बढ़ाने, के लिए तैयार किया गया है। वार्षिक सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान संस्था में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस वर्ष का 'वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी' सम्मान राशिका शर्मा को उनके समर्पण, रचनात्मकता और उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। समारोह में विनोद कुमावत, अंकुर सिंह, अंकित जैन, लोकेश मेहरा, आयुषी पाटनी, शैलेन्द्र सिंह, कुलदीप सिंह, अमित गौतम, संजय कंवरिया तथा रवीना जांगिड़—को भी विभिन्न श्रेणियों में सम्मान प्रदान किया गया।

जयपुर में आबादी के बीच लेपर्ड की दहशत : 48 घंटों में 5 बार दिखा

खबर का महारथी संवाददाता

जयपुर। राजधानी के पॉश इलाके बजाज नगर में लेपर्ड की लगातार मूवमेंट से स्थानीय लोग दहशत में हैं। पिछले 48 घंटों में लेपर्ड अनिता कॉलोनी में 3 बार और एजी कॉलोनी में 2 बार घरों में घुसते और गार्डन में घूमते हुए ष्टष्टञ्जङ्क कैमरों में कैद हुआ है। लेपर्ड एक घर के बाथरूम में रविवार देर रात छुपा मिला, जहां से वह कुछ देर बाद गार्ड की आहट सुनते ही बाहर निकला और दीवार फांदकर फरार हो गया। इससे पहले भी वह कई घरों की दीवारें लांघते हुए दिखाई दिया था। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन लगातार प्रयासों के बावजूद लेपर्ड अभी तक पकड़ से बाहर है। टीम ने आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर कैमरा ट्रैप लगाए हैं। स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है। कई परिवारों ने बच्चों और पालतू जानवरों को घर से बाहर भेजना बंद कर दिया है। वहीं, सोसायटियों में रात के समय सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वन विभाग का कहना है कि लेपर्ड संभवतः भोजन की तलाश में आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचा है। टीम ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और लेपर्ड दिखने पर तुरंत नियंत्रण कक्ष को सूचना दें।

सिलिकोसिस के बढ़ते मामलों पर सांसद मुरारी लाल मीना ने केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की

खबर का महारथी

दौसा। दौसा संसदीय क्षेत्र में सिलिकोसिस बीमारी के बढ़ते मामलों को लेकर सांसद मुरारी लाल मीना ने केंद्र सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। सांसद ने इस मुद्दे को संसद में उठाया और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को पत्र लिखकर दौसा जिले में स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया। सांसद मुरारी लाल मीना ने कहा कि सिलिकोसिस टीबी से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि इसमें मरीज धीरे-धीरे फेफड़ों की क्षमता खो देता है और यह लाइलाज बीमारी है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया कि सिलिकोसिस के लिए भी टीबी की तरह राष्ट्रीय अभियान चलाया जाए। पत्र में सांसद ने बताया कि दौसा जिले के सिकंदरा, सिकराय, गीजगढ़, बहरावंडा, हाईवे के दोनों तरफ़ बंदीकुई, मानपुर सहित अन्य क्षेत्रों में सैंड स्टोन, चेज़ा पत्थर और मार्बल उद्योग की धूल के

कारण हजारों लोग सिलिकोसिस के शिकार हो चुके हैं। कई मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर हैं, और आम परिवार महंगी चिकित्सा खर्च नहीं झेल पा रहे हैं।

सांसद ने केंद्र से निम्नलिखित मांगें की हैं : प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय विशेषज्ञ टीम द्वारा त्वरित सर्वेक्षण, सभी मरीजों के लिए सिलिकोसिस प्रमाणन और राहत राशि ,दौसा में सिलिकोसिस उपचार एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना, सिलिकोसिस प्रभावित राज्यों के लिए केंद्रीय निगरानी तंत्र, हर महीने इलाज के लिए 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता, गंभीर मरीजों के लिए सब्सिडी पर ऑक्सीजन और होम-केयर सुविधाएं, दिवंगत मरीजों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, सिलिकोसिस को राष्ट्रीय प्राथमिकता वाली बीमारी में शामिल करना। सांसद ने कहा कि यह केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि दौसा जिले के सैकड़ों परिवारों के लिए सामाजिक त्रासदी बन चुकी है और इसके समाधान के लिए तत्काल मानवीय कदम उठाना आवश्यक है। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल स्वास्थ्य सचिव और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देंगे, ताकि प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत मिल सके।

सीकर में दर्दनाक हादसा : स्लीपर बस और ट्रक की भिड़ंत में 4 की मौत, 28 घायल

खबर का महारथी संवाददाता

सीकर। जिले के फतेहपुर क्षेत्र में मंगलवार देंर रात जयपुर-बीकानेर नेशनल हाईवे पर स्लीपर बस और तेज रफ्तार ट्रक की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 28 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 6 की हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों में बस ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल हैं। हादसा रात करीब 10:40 बजे हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और कई यात्री सीटों के नीचे व मलबे में फंस गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि जोरदार धमाके के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई।

गुजरात के यात्री वैष्णो देवी से लौट रहे थे

बस में सवार सभी यात्री वलसाड के रहने वाले थे। सभी वैष्णो देवी दर्शन कर लौट रहे थे और खाटूश्यामजी जा रहे थे। बस में करीब 50 लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक झुंझुनूं

की ओर से आ रहा ट्रक तेज रफ्तार में था और सीधे बस में घुस गया। सबसे अधिक चोट बस के आगे वाले हिस्से और उसके पीछे बैठे यात्रियों को आई। कई घायलों के शरीर में शीशे और मेटल के टुकड़े धँस गए। मृतकों में कमलेश ड्राइवर, मयंक यात्री, एक अज्ञात पुरुष, मितेश कंडक्टर शामिल हैं।

घायलों का उपचार जारी

15 गंभीर घायलों को सीकर रेफर किया गया था, जिनमें कई की हालत अब भी नाजुक है। इन्हें सिर, सीने और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। फतेहपुर में 13 घायलों का इलाज चल रहा है, जिन्हें सामान्य चोटें आई हैं। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुँची। बस में फंसे यात्रियों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई यात्री सीटों और टूटी खिड़कियों के बीच फंसे थे। एंबुलेंस ड्राइवर भीम सिंह ने बताया– 'मौके पर पहुंचते ही चारों ओर चीख-पुकार थी। तुरंत अतिरिक्त 108 एंबुलेंस बुलाईं और लोगों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की।' क्षतिग्रस्त बस को क्रेन की मदद से हाईवे से हटाया गया ताकि ट्रैफिक बाधित न हो।

अवैध निमार्ण कार्य पर कार्यवाही के लिए उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

खबर का महारथी संवाददाता

बयाना। विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी बयाना को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि अनुमानित खसरा न0. 2812 गैर मुमकिन टीला है जो कि नगर पालिका कि सिवाचक भूमि है! जिस पर असामाजिक व बाहरी तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर अवेध निर्माण कार्य किया जा रहा है! जो कि आज भी राजस्व विभाग में ये भूमि नगरपालिका कि दर्ज है! इस अवैध निर्माण कार्य के लिये नगर पालिका से किसी भी प्रकार कि निर्माण स्वीकृति नहीं ली गयी है! और ना ही उक्त खसरा नंबर को नगरपालिका बयाना से भूमि रूपांतरण कराया गया है! जो कि एक गैर कानूनी कार्य है ! उक्त खसरा नंबर पर हो रहे अवैध निर्माण व् अतिक्रमण के कारण बाहरी व असामाजिक व्यक्तियों का आये दिन जमावड़ा बना रहता है जिससे व्यवस्था को अव्यवस्थित किया जा रहा है! इन

असामाजिक व्यक्तियों के द्वारा किया जा अवैध निर्माण से क्षेत्र में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई कर निर्माण कार्य बंद करा कर भूमि को नगरपालिका के सुपुर्द किया जाए। इस अवसर पर विश्व हिन्दू परिषद अध्यक्ष जयसिंह फौजदार, उपाध्यक्ष विष्णु जोशी , विशाल उपाध्याय सहसंयोजक बजरंग दल, राजेश चौधरी विश्व हिन्दू परिषद, अरुण सोनी,मनीष सोनी ,लोकेश कौशिक,अन्नू भारद्वाज सहित हिन्दू संगठनों के लोग उपस्थित रहे।

जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही: दो बुजुर्गों के शवों की अदला-बदली, परिजनों ने कर दिया अंतिम संस्कार

खबर का महारथी संवाददाता

अलवर। अलवर जिला अस्पताल में मंगलवार को एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उद्योग नगर और जीआरपी थाना क्षेत्रों से लाए गए दो बुजुर्गों के शवों की अदला-बदली हो गई, जिसके कारण परिजनों ने गलती से दूसरे व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार, उद्योग नगर थाना क्षेत्र की एक झोपड़ी से एक बुजुर्ग का शव मिला और उसे जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। इसी समय जीआरपी थाना क्षेत्र से एक अन्य बुजुर्ग का शव भी मोर्चरी में लाया गया। पहचान के दौरान राजगढ़ थाना क्षेत्र के परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने समझ लिया कि मिला हुआ शव उनका ही है। अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम

कर परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद परिजन ने मृतक का अंतिम संस्कार भी कर दिया। हालांकि, दो दिन बाद जीआरपी थाना पुलिस ने परिजनों को सूचना दी कि उनके परिजन का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में है। यह सुनकर परिजन स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ में आया कि जिला अस्पताल ने उन्हें गलत शव सौंप दिया था। सूचना मिलते ही परिजन हरिद्वार में चल रही अंतिम यात्रा रोककर तुरंत अलवर जिला अस्पताल पहुंचे।

उद्योग नगर थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक लगभग 50-52 साल से घर से बाहर रहकर काम करता था, इसलिए परिजन उसे पहचान नहीं पाए। वहीं, जीआरपी थाना प्रभारी अंजू महिंद्रा ने कहा कि 'हम नियमित प्रक्रिया के तहत 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम करवाते हैं और परिजनों को समय पर सूचना दी गई थी। '

परिजन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर नाराज हैं। उनका कहना है कि शव की स्पष्ट पहचान के बाद ही इसे परिजनों को सौंपना चाहिए था। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार उन्होंने किया, उसमें गरीब परिवार का पैसा भी खर्च हो गया– अब उसका नुकसान कौन भरेगा।

अस्पताल प्रशासन ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस नए सिरे से पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया में जुटी है। प्रशासन और अस्पताल की जिम्मेदारी के सवाल अब पूरे जिले की जनता के सामने हैं, और लोग जानना चाहते हैं कि इस गंभीर लापरवाही पर आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।

रिटायर्ड डिप्टी जेलर के घर बड़ी चोरी : 10 तोला सोना, 1 किलो चांदी और कीमती घड़ी ले उड़े चोर

खबर का महारथी

भरतपुर। चिकसाना थाना क्षेत्र की न्यू पुष्प वाटिका कॉलोनी में मंगलवार देर रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। रिटायर्ड डिप्टी जेलर सुरजीत सिंह के घर चोरों ने धावा बोलकर सोना, चांदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। परिवार उस समय पड़ोस में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने घर को निशाना बनाया। घर खाली देख चोर हुए सक्रिय जानकारी के अनुसार, सुरजीत सिंह किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रूपवास गए हुए थे। घर पर उनकी पत्नी किरनदेई और नातिन मौजूद थीं। रात करीब 9 बजे दोनों पड़ोसी के घर एक समारोह में चली गई और घर को ताला लगाकर वही बैठ गई। इसी दौरान चोरों ने खाली घर का फायदा

उठाते हुए वारदात को अंजाम दिया।

रात 11 बजे लौटा परिवार, टूटा ताला देख उड़े होश

रात करीब 11 बजे जब सुरजीत सिंह घर वापस लौटे और पत्नी के साथ अंदर प्रवेश किया तो मुख्य गेट का ताला टूटा देखकर उनके होश उड़ गए। घर में प्रवेश करने पर अलमारियां खुली मिलीं और सामान इधर-उधर बिखरा हुआ था। तलाशी लेने पर पता चला कि चोर 10 तोला सोना, 1 किलो चांदी के जेवर, लगभग 15 हजार रुपये की कीमती घड़ी तथा अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए हैं।

पुलिस मौके पर, जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू

घटना की सूचना मिलते ही चिकसाना थाना पुलिस मौके पर पहुँची और पूरे घटनास्थल का जायज़ा लिया। पुलिस ने बताया कि वारदात बेहद सुनियोजित लग रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि चोरों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके।

इलाकेवासियों में दहशत का माहौल

रिहायशी कॉलोनी में हुई इस बड़ी चोरी की घटना से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं, पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही चोरों को पकड़कर मामला सुलझा लिया जाएगा।

खान एवं पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा बैठक : अवैध खनन में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा - सीएम भजनलाल शर्मा

खबर का महारथी संवाददाता

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन उपलब्ध होने से यह क्षेत्र राज्य के विकास में महती भूमिका निभाता है। साथ ही, यह क्षेत्र स्थानीय रोजगार एवं क्षेत्रीय विकास की भी अहम कड़ी है। हमारी सरकार प्रदेश को खनन क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनिज संसाधनों का समुचित दोहन करते हुए समयबद्ध राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। साथ ही, प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाए। शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में खान एवं पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में असीम खनिज संपदा

की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नए खनिज ब्लॉक्स की पहचान की जाए। साथ ही, अत्याधुनिक नवाचार एवं एआई का उपयोग करते हुए नए खनिज ब्लॉक्स की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि खनिज संपन्न राज्यों में खान क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों एवं राजस्व वृद्धि के लिए किए जा रहे कार्यों का अध्ययन किया जाए जिससे राजस्व में वृद्धि की जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन क्षेत्र में बड़ी संख्या में कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि रोजगार को बढ़ावा देते हुए प्रदेश में वैध खनन को बढ़ावा दिया जाए, अवैध खनन पर अंकुश लगे। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में नीलामी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए तथा पुलिस, परिवहन एवं खान विभाग आपसी समन्वय कर अवैध खनन की रोकथाम के लिए कार्ययोजना बनाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध खनन निर्धारण के लिए क्षेत्र में ड्रोन सर्वे को बढ़ाया जाए। साथ ही, खनन पट्टा क्षेत्रों एवं अवैध खनन स्थलों की जियो फैन्सिग को और प्रभावी बनाया जाए।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बजरी के विकल्प के रूप में एम-सेण्ड के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए एम-सेण्ड नीति 2024 जारी की गई है। इस नीति के माध्यम से एम सैंड यूनिट लगाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया गया है जिससे एम-सेण्ड के लिए प्रदेश में अनेक प्लांट्स संचालित हैं। उन्होंने अधिकारियों को इन सभी प्लांट्स की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में खनिज संसाधनों की संभावनाओं को जानने के लिए भी प्रभावी कार्ययोजना बनाए जाने के भी निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि खान विभाग द्वारा एम-सेण्ड पॉलिसी, मिनरल डवलपमेंट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और अवैध माइनिंग मॉनिटरिंग कमेटी का गठन, ई-रवन्ना, ई-टीपी के गलत इस्तेमाल के लिए टीम का गठन तथा अवैध खनन संवेदनशील क्षेत्रों में बॉर्डर होम गार्ड की तैनाती जैसे कार्य किए गए हैं। साथ ही, प्रदेश में खनन से रॉयल्टी वृद्धि हेतु खनिज परिवहन के लिए जीपीएस एवं आरएफआईडी युक्त वाहनों की बाध्यता की जा रही है। समस्त विभागीय एमपैनल्ड वे-ब्रिज पर स्टेण्डर्ड सॉफ्टवेयर का उपयोग, तुलायंत्रो पर सैंसर्स, ए.आई. कैमरा सहित विभिन्न नवाचार किए गए हैं। इससे पहले प्रमुख शासन सचिव खान टी. रविकांत ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से खान एवं पेट्रोलियम विभाग के नवाचारों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

श्यालावास जेल में बंदियों ने प्रवासी राजस्थानी दिवस पर बनाई अद्भुत सैंड आर्ट

खबर का महारथी संवाददाता

जयपुर। दौसा की विशिष्ट केंद्रीय कारागृह श्यालावास में बंदियों के भीतर छिपी रचनात्मक ऊर्जा मंगलवार को एक भव्य कलाकृति के रूप में सामने आई। जेल अधीक्षक पारस जांगिड की प्रेरणा से बंदियों ने प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर 2025 को समर्पित करते हुए जेल परिसर के उद्यान क्षेत्र में एक अत्यंत सुंदर और प्रतीकात्मक सैंड आर्ट का निर्माण किया। यह कलाकृति राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, उसके जीवंत रंगों और गौरवशाली इतिहास को एक अनूठे रूप में प्रदर्शित करती है। इस आकर्षक सैंड आर्ट में दिवस के लोगो के अनुरूप राजस्थान की पहचान माने जाने वाली पारंपरिक झरोखा शैली को प्रमुखता से उकेरा गया है। इसके साथ ही कलाकृति में राज्य का स्पष्ट नक्शा, मरुभूमि के जहाज कहे जाने वाले ऊँटों की

आकृतियाँ तथा अनेक रंग-बिरंगे सांस्कृतिक प्रतीकों को अत्यंत बारीकी और कुशलता से दर्शाया गया है। बंदियों ने इस कलाकृति के निर्माण के लिए मिट्टी, प्राकृतिक रंगों और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग किया, जो उनकी रचनात्मकता और सकारात्मक परिवर्तन की भावना को दर्शाती है।

सैंड आर्ट का विमोचन करते हुए उप निदेशक उद्योग पीयूष अग्रवाल ने बंदियों के प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह कलाकृति राजस्थान की अमूल्य धरोहर, मरु-संस्कृति और अपनी मिट्टी से जुड़े गर्व को सुंदर रूप में प्रस्तुत करती है। अग्रवाल ने कला को पुनर्वास का एक सशक्त माध्यम बताते हुए जोर दिया कि ऐसे रचनात्मक प्रयास बंदियों के जीवन में नया आत्मविश्वास और सम्मान की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मूर्तिकार राजेश शर्मा, संदीप अग्रवाल, महेश शाह और राजाराम जैसे बंदियों ने रंग योजना, डिजाइन और उभार तकनीक पर कई दिनों तक अथक मेहनत की, जिसके परिणाम स्वरूप यह अद्भुत कलाकृति बन पाई। यह सृजनात्मक पहल न सिर्फ प्रवासी राजस्थानी दिवस को एक सुंदर श्रद्धांजलि है, बल्कि यह एक सशक्त संदेश भी देती है कि यदि सही दिशा और प्रेरणा मिले, तो हर व्यक्ति अपनी कलात्मक ऊर्जा को समाजोपयोगी बनाकर एक नई राह पर चल सकता है। इस अवसर पर शिवांगन स्पिनर के महाप्रबंधक किशन सिंह भाटी, जेलर दिलावर ख़ान, ओम प्रकाश शर्मा और प्रकाश शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

बीएलओ-सुपरवाइजर सम्मानित : रिटर्निंग अधिकारी बोले सामूहिक प्रयासों से मिली बड़ी सफलता

खबर का महारथी संवाददाता

लालसोट। उपखंड मुख्यालय पर लाड पैलेस में आयोजित सम्मान समारोह में लालसोट विधानसभा क्षेत्र के 263 बीएलओ, सुपरवाइजरों एवं तहसीलदारों का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समय से पूर्व एसआईआर अभियान में 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने वाले कार्मिकों को सम्मानित करना रहा। समारोह को संबोधित करते हुए एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी विजेंद्र मीणा ने कहा कि लालसोट विधानसभा क्षेत्र ने जिले में सबसे पहले निर्धारित समय से पहले एसआईआर अभियान का लक्ष्य हासिल कर एक अनूठा कीर्तिमान

स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ ने तनावमुक्त होकर पूरी निष्ठा व लगन से कार्य किया, वहीं सहायक निर्वाचन अधिकारी, तहसीलदार और सुपरवाइजरों ने भी बीएलओ के समक्ष आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान कर सुगमता बनाए रखी। उन्होंने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को पूरी टीम की सामूहिक सफलता बताया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी रामगढ़ पचवारा बद्रीनारायण मीणा, तहसीलदार सीमा गुनावत, तहसीलदार राहुवास, तहसीलदार रामगढ़ पचवारा, अधिशासी अधिकारी मंडावरी, नगर परिषद आयुक्त नवरत्न शर्मा सहित रमेश चंद्र शर्मा, वीरेंद्र जैन, कमलेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में बीएलओ, सुपरवाइजर एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर एसडीएम तथा रिटर्निंग अधिकारी विजेंद्र मीणा सहित अन्य कार्मिकों ने भी डीजे की धुन पर डांस कर खुशी का इजहार किया।

कृषि विभाग की कार्रवाई: अवैध परिवहन के दौरान 194 बैग यूरिया जब्त

खबर का महारथी संवाददाता

डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले में किसानों के लिए निर्धारित यूरिया खाद की कालाबाजारी और अवैध परिवहन करने वालों के विरुद्ध कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) डूंगरपुर परेश कुमार पण्ड्या के निर्देश पर गठित टीम ने निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से ले जाए जा रहे 194 बैग यूरिया खाद जब्त किए हैं। यूरिया की कमी के दौरान अवैध परिवहन, जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, संयुक्त निदेशक कृषि ने जिले के विभिन्न ब्लॉकों पर विशेष टीम गठित कर त्वरित कार्वाई के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों की

अनुपालना में, सहायक निदेशक कृषि गीता रोत ने सीमलवाड़ा ब्लॉक में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने अवैध परिवहन कर ले जाए जा रहे यूरिया खाद के 194 बैग पकड़े। यह कार्रवाई उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो किसानों के हितों की अनदेखी करते हुए आवश्यक कृषि सामग्री की कालाबाजारी में संलिप्त हैं।

अवैध रूप से यूरिया का परिवहन करते पकड़े जाने पर, सहायक निदेशक कृषि गीता रोत ने जब्त यूरिया के संबंध में संबंधित वाहन चालक के विरुद्ध तत्काल धम्बोला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। कृषि विभाग की यह सक्रियता सुनिश्चित करती है कि किसानों को समय पर और सही दाम पर खाद उपलब्ध हो सके, तथा अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

ग्राम विकास अधिकारी 1,500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

खबर का महारथी

पाली। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी पाली-प्रथम इकाई ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत मुसालिया, पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी कान्ता शर्मा को 1,500 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जन्म प्रमाण पत्र में आधार नंबर दर्ज कराने की एवज में मांगी रिश्वत एसीबी पाली-प्रथम चौकी को प्राप्त शिकायत के अनुसार, आरोपी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादी के पुत्र और पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में माता-पिता के आधार नंबर दर्ज करने के लिए 3,000 रुपये

रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा था। शिकायत की पुष्टि के बाद ब्यूरो ने कार्रवाई की तैयारी शुरू की।

जोधपुर रेंज के उप महानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरवीजन और एसीबी पाली-प्रथम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र डुकिया के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई संचालित की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी कान्ता शर्मा को 1,500 रुपये रिश्वत रकम स्वीकार करते हुए दबोच लिया गया। आरोपी से पूछताछ जारी है तथा मामले में आगे की जांच एसीबी द्वारा की जाएगी।

खबर का महारथी
Web: khabarkamaharathi.com

न्यूज ब्रीफ

एसआईआर के दूसरे चरण में अब तक 99.18 प्रतिशत फॉर्म डिजिटाइज्ड

खबर का महारथी

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक का एसआईआर के दूसरे चरण का विस्तृत बुलेटिन जारी किया। 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 4 नवंबर से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स द्वारा मतदाताओं से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर डिजिटल रूप से दर्ज की जा रही है। चुनाव आयोग ने बताया कि 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 50.99 करोड़ से अधिक मतदाता सूची में शामिल हैं और अब तक 99.97 प्रतिशत एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण और 99.18 प्रतिशत का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों ने 100 प्रतिशत एन्यूमरेशन फॉर्म वितरण कर दिया है। वहीं, इन राज्यों में फॉर्म डिजिटाइजेशन की बात करें तो लक्षद्वीप में 100 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 100 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 99.96 प्रतिशत और गुजरात में 99.94 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है।

वोटर संख्या सबसे अधिक होने के बावजूद बड़े राज्यों ने भी उल्लेखनीय गति से अपडेट पूरा किया है। उत्तर प्रदेश में 15.44 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 99.97 प्रतिशत फॉर्म वितरण और 98.14 प्रतिशत डिजिटाइजेशन हो चुका है। तमिलनाडु में 99.95 प्रतिशत फॉर्म वितरण और 99.55 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 99.99 प्रतिशत वितरण और 99.75 प्रतिशत डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आयोग ने बताया कि एसआईआर के कार्य के लिए 5,33,096 बीएलओ तैनात किए गए हैं। 12,43,716 बीएलए की नियुक्ति की गई है। 50,95,77,592 फॉर्म वितरित किए गए हैं और 50,58,01,033 फॉर्म डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। 11 दिसंबर को एसआईआर प्रक्रिया का दूसरा चरण समाप्त होगा, जिसके बाद डेटा सत्यापन और अंतिम सूची तैयारी की प्रक्रिया शुरू होगी। देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में यह तेज रफ्तार एसआईआर प्रक्रिया एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने गरीबों को 95.5 लाख घर दिए

खबर का महारथी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की दो स्कीमों के तहत लाभार्थियों को 95.54 लाख घर दिए गए। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने संसद को यह जानकारी दी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सप्लीमेंट्री सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि 2020 के एक स्लम सर्वे से पता चला है कि देश भर में 1.39 करोड़ घरों वाले 6.5 करोड़ लोग स्लम में रह रहे थे। उन्होंने बताया कि जमीन और कॉलोनी बनाना राज्य के विषय हैं और स्लम रिहैबिलिटेशन से जुड़ी पॉलिसी और प्रोग्राम संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास हैं। इसलिए, स्लम रिहैबिलिटेशन या रीलोकेशन से जुड़ा डेटा मंत्रालय नहीं रखता है। हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में झुग्गी पुनर्वास और विध्वंस कार्य विभिन्न भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियों जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड आदि द्वारा विभिन्न लागू अधिनियमों के प्रावधानों के तहत किए जाते हैं।

मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा, 'अपने स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत, डीडीए ने योग्य झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों का ठीक से रिहैबिलिटेशन करने के बाद तोड़-फोड़ की है। इसमें कुल 5,158 परिवार शामिल हैं, जिनमें से कुल 3,414 डीयूएसआईबी पॉलिसी के अनुसार दूसरे रिहैबिलिटेशन के लिए योग्य पाए गए। '

पात्र निवासियों को सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ वैकल्पिक पुनर्वास प्रदान किया गया है। मंत्री ने बताया कि झुग्गी-झोपड़ी के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के दौरान, जमीन मालिक एजेंसियां, लागू करने वाली एजेंसियां और प्रभावित परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा- देश अब पूरी तरह से 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' फेज में

खबर का महारथी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल के नेताओं से कहा कि भारत पूरी तरह से 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' चरण में आ गया है, जिसमें तेज और नागरिकों केंद्रित शासन बदलाव होंगे। सांसदों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सिर्फ आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने या रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी को असल में आसान बनाने के लिए रिफॉर्म कर रही है। उन्होंने कहा, 'हमारा लक्ष्य नागरिकों के सामने आने वाली रोजमर्रा की मुश्किलों को दूर करना है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें।' उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे जनता की ओर से लाए गए जमीनी मुद्दों को सक्रिय रूप से शेयर करें, ताकि सरकार उन्हें तेजी से हल कर सके।

पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकार उन नौकरशाही रुकावटों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है जो नागरिकों पर बोझ डालती हैं, जिनमें लंबे आवेदन फॉर्म और बार-बार होने वाले पेपरवर्क शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद एक ऐसे सिस्टम की ओर बढ़ना है जहां सर्विस लोगों के घर तक पहुंचाई जाएं, जिससे अलग-अलग विभाग में एक ही डेटा बार-बार जमा करने की जरूरत खत्म हो जाए।

अलग-अलग सेवाओं और योजनाओं के लिए स्वयं प्रमाणन की इजाजत देने के सरकार के फैसले को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बदलाव नागरिकों के भरोसे पर आधारित है। एक ऐसा भरोसा जो पिछले 10 सालों से मजबूत बना हुआ है। इससे पहले, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी एनडीए सांसदों ने बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी को बधाई दी। मंगलवार को एनडीए संसदीय पार्टी की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए, रिजिजू ने कहा, 'संसदीय पार्टी की मीटिंग में एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की माला पहनाकर सम्मानित किया गया और बिहार इलेक्शन में शानदार जीत के लिए बधाई दी गई।' उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने मीटिंग के दौरान राज्य और इलाके के लिए काम करने के तरीके पर मार्गदर्शन किया।

नेहरू ने वंदे मातरम के दो टुकड़े किए, यह तुष्टीकरण देश के विभाजन में बदला : अमित शाह

खबर का महारथी संवाददाता

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा प्रारंभ की। वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में राज्यसभा में यह चर्चा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि यह तो वंदे मातरम का 150वां साल है। हर महान रचना का महत्वपूर्ण साल हमारे देश में मनाया जाता है। जब वंदे मातरम के 50 वर्ष हुए थे तब क्या हुआ था? तब देश आजाद नहीं हुआ था। वर्ष 1937 में वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई थी। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के दो टुकड़े करके उसे दो अंतरों तक सीमित करने का काम किया था। केन्द्रीय गृह मंत्री मंत्री ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि 50वें वर्ष में वन्दे मातरम को सीमित कर दिया गया; वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई। वह तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में बदला। उन्होंने कहा, 'मेरे जैसे कई लोगों का मानना है कि तुष्टीकरण की नीति के कारण यदि वंदे मातरम के दो टुकड़े नहीं करते हैं तो देश का बंटवारा नहीं होता। '

अमित शाह ने कहा यदि ऐसा नहीं किया जाता तो आज देश पूर्ण होता। सबको यकीन था कि वंदे मातरम के 100 साल मनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम बोलने वाले सभी लोगों को इंदिरा गांधी ने जेल भेज दिया। देश में आपातकाल लगाया गया और लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया। विपक्ष के लोगों को, स्वयंसेवी संगठन के लोगों को जेल भेज दिया गया। अखबार के दफ्तरों पर ताले लगाए गए।

अमित शाह ने सदन को जानकारी देते हुए कहा था कि जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए तो पूरे देश को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जब वंदे मातरम के 150 साल पर लोकसभा में चर्चा हुई, तो यहां पर कांग्रेस की स्थिति देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों की शुरुआत गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर वंदे मातरम गाकर करवाते थे, जो गीत कांग्रेस पार्टी की आजादी की लड़ाई का एक मंत्र बना था, उसका महिमामंडन करने के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई तो गांधी परिवार के दोनों सदस्य सदन से नदारद रहे।

उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व के खून के अंदर है। इस दौरान कांग्रेस समेत विपक्ष के दलों ने अमित शाह के इस वक्तव्य पर अपनी नाराजगी जताते हुए अपना विरोध किया। केंद्रीय गृहमंत्री ने लोकसभा का हवाला देते हुए बताया कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि वंदे मातरम पर चर्चा की आज कोई जरूरत नहीं है। यह पूरी बात रिकॉर्ड पर है।

अक्टूबर में 44 देशों से 2,501 नए एमपॉक्स मामले की पुष्टि, 12 मौतों की रिपोर्ट : डब्लूएचओ

खबर का महारथी संवाददाता

नई दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को कहा कि अक्टूबर में 44 देशों से एमपॉक्स के कुल 2,501 नए मामले सामने आए, जिनमें 12 मौतें भी शामिल हैं। एमपॉक्स के कई देशों में फैले प्रकोप की नवीनतम स्थिति रिपोर्ट से पता चला है कि मंकीपॉक्स के सभी क्लेड अभी भी फैल रहे हैं। जब एमपॉक्स के प्रकोप को तेजी से कंट्रोल नहीं किया जाता है और इंसान से इंसान में फैलने को रोका नहीं जाता है, तो लगातार सामुदायिक प्रसारण का खतरा रहता है। डब्लूएचओ की रिपोर्ट में कहा गया है, 'अक्टूबर 2025 में, डब्लूएचओ के सभी क्षेत्रों के 44 देशों ने कुल 2,501 नए एमपॉक्स मामलों की पुष्टि की, जिसमें 12 मौतें शामिल हैं।' अफ्रीका के 21 देशों ने पिछले छह हफ्तों 12 अक्टूबर से 23 नवंबर तक में एमपॉक्स की सक्रियता की सूचना दी, जिसमें 1,734 की पुष्टि मामले और 10 मौतें शामिल हैं।

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लाइबेरिया, घाना, केन्या और युगांडा में सबसे ज्यादा मामले सामने आए, जबकि माली में पहली बार एमपॉक्स की सूचना मिली। बेल्जियम, जर्मनी, ग्रीस और ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम में यात्रियों के बीच क्लेड आईबी एमपीएक्सवी के कारण एमपॉक्स के नए इंपोर्टेड मामले सामने आए।

5 सितंबर से 24 नवंबर के बीच, छह डब्ल्यूएचओ क्षेत्रों में क्लेड आईबी एमपीएक्सवी के कारण एमपॉक्स के कुल 43 नए सक्रिय मामले सामने आए हैं, उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां इस वायरस स्ट्रेन का लगातार सामुदायिक प्रसार हो रहा है। इनमें से चार क्षेत्रों अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और पश्चिमी प्रशांत में, 24 मामलों में हाल ही में कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नहीं की गई थी, जो स्थानीय प्रसार का संकेत देता है।

इसके आधार पर इटली, मलेशिया, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और अमेरिका को अब क्लेड आईबी एमपीएक्सवी के सामुदायिक प्रसार का अनुभव करने वाला माना जा रहा है। इसके अलावा, कई देशों में यात्रा से संबंधित मामले सामने आ रहे हैं। एमपॉक्स को मंकीपॉक्स भी कहा जाता है, एक वायरल बीमारी है जो करीबी संपर्क से फैलती है। इसके लक्षणों में बुखार, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते और पीठ दर्द शामिल हैं। यह मुख्य रूप से स्किन-टू-स्किन संपर्क से फैलता है।

संसद का शीतकालीन सत्र : चुनाव सुधारों पर राहुल गांधी बोले- चुनाव आयोग पर कब्जा किया जा रहा

खबर का महारथी संवाददाता

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान लोकसभा में राजनीतिक माहौल गर्म रहा। लाइव प्रसारण के बीच नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने संबोधन में लोकतंत्र, वोट और भारत की विविधता पर विस्तृत बात रखी। राहुल गांधी ने कहा, आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है। चुनाव आयोग कब्जा किया जा रहा, चुनाव में भाजपा इसका इस्तेमाल कर रही है।राहुल ने कहा, 'ED, सीबीआई, IB, Income टैक्स डिपार्टमेंट पर कब्जा किया जा रहा है और ये सब RSS कर रहा है। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर SIR के बहाने अंदर ही अंदर NRC वाला काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने सिर्फ़ एक साधारण कपड़े की बात नहीं की थी, बल्कि 'खादी' को भारत की भावना, कल्पना और लोगों की उत्पादक शक्ति का प्रतीक बनाया था। उन्होंने कहा, 'खादी सिर्फ कपड़ा नहीं है, यह भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति है।' उन्होंने देश की सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण देते हुए हिमाचली टोपी, असमिया गमछा, बनारसी साड़ी, कांचीपुरम साड़ी और नागा जैकेट का ज़िक्र किया। राहुल गांधी बोले कि इन वस्त्रों में हज़ारों धागे एक-दूसरे को गले लगाते हैं—और किसी एक धागे की महत्ता दूसरे से ज़्यादा नहीं होती। कांग्रेस नेता ने कहा, 'धागे अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब वे साथ आते हैं तो एक मजबूत कपड़ा बनता है, जो सुरक्षा देता है, गर्मी देता है और पहचान देता है। उसी तरह भारत भी 1.4 बिलियन लोगों से बनी एक विशाल चादर है।' उन्होंने कहा कि यह 'कपड़ा' केवल वोट से बुना जाता है। वोट ही लोकतांत्रिक संस्थाओं का आधार है—लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएँ और पंचायतें—all exist because people vote. राहुल गांधी के इस भाषण के बाद विपक्षी बेंचों ने टेबल थपथपाकर समर्थन दिखाया, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी बीच-बीच में प्रतिक्रिया देखने को मिली। चुनाव सुधारों पर चर्चा सत्र के दौरान जारी है।

बंगाल-असम-यूपी की SIR प्रक्रिया पर 'सुप्रीम' सुनवाई, केंद्र-चुनाव आयोग को नोटिस जारी

खबर का महारथी

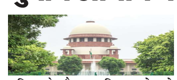

नई दिल्ली। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पात्र लोगों की नागरिकता प्रक्रिया और कई राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठी चिंताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को तीन अलग-अलग याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। पहली याचिका में कहा गया है कि भारत में लंबे समय से रह रहे हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदायों के लोग सीएए के तहत नागरिकता के हकदार हैं। इनमें से कई लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन भी किया है, लेकिन उनके मामलों में अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता का दावा है कि इस देरी की वजह से अब उनके नाम वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया के दौरान शामिल न हो पाने का खतरा बढ़ गया है। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दूसरी याचिका भारतीय किसान यूनियन आजाद ट्रस्ट ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के लिए दिया गया 4 हफ्ते का समय प्रशासनिक रूप से बिल्कुल अपर्याप्त है। याचिका में तर्क दिया गया है कि यूपी में 15.35 करोड़ मतदाता हैं। इतने बड़े राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को महज चार सप्ताह में पूरा करना असंभव है। कम समय की वजह से बड़े पैमाने पर वैध मतदाताओं के नाम कटने का खतरा पैदा हो गया है।

ट्रस्ट ने यह भी बताया कि उसने पहले चुनाव आयोग को समय बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। तीसरा मामला असम से जुड़ा है। यहां एसआईआर की बजाय केवल स्पेशल रिवीजन कराने के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि असम जैसे संवेदनशील राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है और इसे एसआर से बदलना अनेक विसंगतियों को जन्म देगा। इस याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इस मामले में भी 16 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।

एआई भविष्य पर बड़ा दांव, भारत में 1.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी माइक्रोसॉफ्ट

खबर का महारथी

नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बुनियादी ढांचे, कौशल और संप्रभु क्षमताओं के निर्माण में मदद के लिए 17.5 अरब डॉलर या 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस क्रम में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और सीईओ सत्य नडेला ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सत्य नडेला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट 17.5 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है, जो एशिया में हमारा अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, ताकि भारत के एआई-प्रधान भविष्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, कौशल और संप्रभु क्षमताओं के निर्माण में मदद मिल सके। इससे पहले अमेरिकी टेक दिग्गज ने जनवरी में भारत में अगले दो वर्षों में क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वह अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को एआई कौशल का प्रशिक्षण देकर देश की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देगा।

नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ा नाम? सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

खबर का महारथी

नई दिल्ली। बिना भारतीय नागरिकता हासिल किए मतदाता सूची में नाम शामिल कराने से जुड़े मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। यह नोटिस वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दायर रिवीजन पिटीशन पर जारी किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 जनवरी, 2026 को होगी। वकील विकास त्रिपाठी का कहना है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में शामिल था, जबकि उन्होंने 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिकता हासिल की। इसी आरोप के आधार पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग की गई थी, लेकिन सितंबर 2025 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देते हुए त्रिपाठी ने रिवीजन पिटीशन दाखिल की, जिस पर अब राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है।

दाखिल याचिका में कहा गया है कि 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम कैसे शामिल हुआ, जबकि तब तक उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की थी। याचिका में यह भी पूछा गया है कि 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया था, तो आखिर किन कारणों से यह कार्रवाई हुई?

याचिका में यह भी कहा गया कि यदि 1983 में ही नागरिकता मिली, तो 1980 में नाम शामिल कराने के लिए किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया? क्या उस समय फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया गया? राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वे आरोपों पर विस्तृत जवाब दाखिल करें। बता दें कि इससे पहले, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर 2025 में दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच कराने की मांग की गई थी। बाद में, इसी आदेश को चुनौती देते हुए रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट ने अब जवाब मांगा है।

भारत-रूस की बढ़ती नजदीकियों से ट्रंप नाराज, अब भारतीय चावल पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी

खबर का महारथी

नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के भारत दौरे ने एक बार फिर दोनों देशों की दशकों पुरानी दोस्ती को वैश्विक मंच पर मजबूत तरीके से पेश किया। लेकिन यह बढ़ती निकटता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आई। अमेरिका पहले ही भारत पर कुल 50% तक का टैरिफ लगा चुका है—जिसमें रूसी तेल खरीद पर लगाया गया अतिरिक्त 25% शुल्क भी शामिल है। अब ट्रंप ने भारत के चावल निर्यात पर भी नया टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। यह विवाद तब उभरा जब व्हाइट हाउस में ट्रंप ने अमेरिकी कृषि व किसानों से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। लुइसियाना की प्रमुख चावल उत्पादक मेरिल केनेडी ने ट्रंप को बताया कि भारत, थाईलैंड और चीन अमेरिकी बाजार में सस्ते दामों पर चावल डंप कर रहे हैं, जिससे अमेरिकी किसान मुश्किल में हैं। ट्रंप ने तुरंत सवाल उठाया—'भारत को ऐसा करने की अनुमति क्यों है? उन्हें शुल्क देना होगा।' उन्होंने संकेत दिया कि चावल पर अतिरिक्त टैरिफ लगाकर इस समस्या को एक दिन में हल किया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने जानकारी दी कि भारत के साथ इस समय व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है और वैश्विक बाजार में करीब 30% हिस्सेदारी रखता है। सोना मसूरी सहित कई भारतीय किस्में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में लोकप्रिय हैं। ऐसे में यदि अमेरिका भारतीय चावल पर नया टैरिफ लगाता है, तो यह न सिर्फ भारत के निर्यातकों बल्कि वैश्विक चावल बाजार के लिए भी बड़ा झटका साबित हो सकता है। रूस-भारत ऊर्जा साझेदारी पहले ही अमेरिका को असहज कर रही है। अब चावल विवाद ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को और बढ़ा दिया है।

मुद्रक बृजमोहन शर्मा तथा प्रकाशक बृजमोहन द्वारा बृजमोहन शर्मा के पक्ष में मोहन शर्मा एण्ड प्रा.लि.ए-9, ग्राउन्ड फ्लोर, सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र, बाईस गोदाम, जयपुर से मुद्रित तथा ग्राम-रामसर पालावाला, पोस्ट-जीतावाला, तहसील- बस्सी, जिला- जयपुर (राज.) से प्रकाशित, संपादक बृजमोहन शर्मा।